रजिस्टढं नं 0 पी 0/एस 0 एम 0 14.



राजपत्न, हिमाचल प्रदेश (मसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 26 धप्रैल, 1986/6 वैवाख, 1908

हिमाचल प्रवेश सरकार

विधि विभाग (ग्रनुवाद कक्ष)

ग्रधिसूचनाएं

शिमला-2, 4 फरवरी, 1986

सं0 डी0 एल0 श्रार0-अनुवाद श्रिधिप्रमाणन-6/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) श्रिधिनयम, 1981 (1981का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव प्रसैम्बली मैम्बर्ज (रिमूवल ग्राफ डिसक्वालिफिकेशन) ऐक्ट, 1971 के ग्रधि-प्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्त, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं ग्रीर यह उक्त ग्रिधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेग।

श्रादेश द्वारा, कुलदीप चन्द सूद, सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहंताएं हटाना) श्रधिनियम, 1971

(1971 का भ्रधिनियम संख्यांक 7)

(20 प्रक्तूबर, 1984 को यथा विद्यमान)

(22 ग्रजैल, 1971)

भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के ग्रधीन कुछ लाभ के पदों को, उनके घारकों को, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जान या होने के लिए निर्राहत न करने वाला घोषित करने के लिए श्रधिनियम ।

भारत गणराज्य के बाईसर्वे वर्ष में हिमाचल ऋदेश विधान सभा द्वारा निम्तलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- 1. (1) इस ग्रधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान समा सदस्य संक्षिप्त नाम (निरहेताएं हटाना) ग्रधिनियम, 1971 है। ऋौर प्रारम्भ ।
 - (2) यह त्रन्त प्रवृत्त होगा ।
 - 2. इस म्रधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से मन्यया म्रपेक्षित न हो,-

परिभाषाएं।

- (क) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से ऐसी धन राजि अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा किसी पद के धारक को उस पद के क़त्यों को करने के प्रयोजन के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, ब्रासीन भता, वाहन भता या गृह किराया भत्ता के हा में संदेय श्रवधारित की जाए;
- (ख) "कानुनी निकाय" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के ग्रधीन स्थापित कोई निगम, समिति, ग्रायोग, परिषद, बोर्ड या ग्रन्य व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित है या नहीं ;
- (ग) "श्रकानुनी निकाय" से कानुनी निकाय से भिन्न व्यक्तियों का कोई निकाय श्रिभित्रेत है।
- 3. कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने ग्रौर हिमाचल होने के लिए केवल इस तथ्य के ग्राधार पर निर्द्त नहीं होगा कि वह भारत सरकार प्रदेश की या किसी राज्य सरकार के प्रधीन निम्नलिखित लाभ के पदों में से किसी का धारक विधान सभा है :---

की सदस्यता के लिए निर-**ह**ताश्रों हटाना ।

- (क) उप-मन्त्री या राज्य मन्त्री का पद;
- (ख) किसी मन्त्री, राज्य मन्त्रीया उप-मन्त्री द्वारा चाहे पदेन या नाम से धारित
- (ग) हिमाचल प्रदेश विघान सभा या संसद या किसी श्रन्य राज्य की विघान

सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद;

(घ) मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव का पद ;

(ङ) किसी विधान सभा में या संसद में मुख्य सचेतक, उप-मुख्य सचेतक या

ं सचेतक का पद;

(च) ग्राम राजस्व ग्रधिकारी का पद, नाहे उसका नाम लम्बरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख हो या कोई ग्रन्य नाम हो, जिसका कर्नव्य भू-राजस्व का संग्रह करना है ग्रौर जिसका पारिश्रमिक उसके द्वारा संग्रहीत भू-राजस्व की रकम में से ग्रंश के रूप में या उस पर कमीशन के रूप में दिया जाता है किन्तु जो कोई पुलिस कृत्य नहीं करता है;

(छ) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राष्ट्रीय कैंडेट कोर, प्रादेशिक सेना, वायु

रक्षा रिजर्व ग्रीर सहायक वायु सेना में कोई पद;

(ज) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद;

- (अ) किसी विश्वविद्यालय के अभिषद, वरिष्ट सभा, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या सभा के या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के अध्यक्ष या सदस्य का पद;
- (जा) किसी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का पद;
 - (ट) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा भारत से बाहर भेजे गए या हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य से बाहर किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए भेजे गए किसी शिष्टमण्डल या मिशन के सदस्य का पद;
 - (ठ) लोक महत्व के किसी विषय की बाबत सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी विषय में जांव क ने या उस की वाबत अकिड़े संग्रहीत करने के प्रयोजन के लिए अस्थाई क्य से स्थापित किसी समिति के (वाहे वह एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी हो) अध्यक्ष या सदस्य का पद; यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से मिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है;
- (ड) ऐसे निकाय से भिन्न, जो खण्ड (ठ) में निर्दिष्ट है किसी कानूनी या भकानूनी निकाय के श्रष्टमक्ष या उपाध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है;
- (द) सरकारी प्रवन्ध के अधीन किसी अस्पताल में अवैतनिक स्वास्थ्य अधिकारी या अवैतनिक सहायक स्वास्थ्य अधिकारी का पद;
- (म) भ्रपनी सेवा पेंन्शन, राजनीतिक पेंन्शन या अनुदान, मनसब, पूर्व अनुदान या किसी जागीर की वाबत किसी प्रतिकर की संराशिकरण राशि, इनाम या भन्य अनुदान लेने वाला कोई व्यक्ति;
- (त) ऐसे कमीशन के लिए जो केन्द्रीय सरकार ने इस निमित निर्धारित किया हो, या बिना कमीशन के राष्ट्रीय योजना पत्नों या किन्हीं अन्य बचत पत्नों या ऐसे किसी अन्य बचत-पत्नों, या सरकारी प्रतिभूतियों का जो उस रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रीधमूचित की जाए विक्रय करने या इसके लिए श्रीभदान का संग्रह करने के प्रयोजन के लिए श्रीभकर्ता का पद या इसी प्रकार का अन्य पद;
- (य) केर्द्राय या राज्य सरकार द्वारा या संघ लोक सेवा ग्रायोग या किसी राज्य सोक सेवा ग्रायोग द्वारा ली गई किसी परीक्षा के किसी परीक्षक का पद;
- (द) तत्ममय प्रवृत्त किसी विधि के श्रधीन सरपंच या किसी पंचायत के सदस्य का पद; भौर

- (ध) इस धारा के खण्ड (ठ) ग्रीर (ड) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति आयोग के ग्राध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद या राज्य सरकार द्वारा गठित हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद।
- 4. इस ग्रधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उठे इस प्रश्न का ग्रवधारण कि कोई पद अधिनियम के भारत सरकार या राज्य सरकार के श्रधीन लाभ का पद है या नहीं उसी प्रकार किया जाएगा मानों कि इस श्रधिनियम के उपबन्ध सभी तात्विक तारीखों को प्रवृत्त थे।

प्रारम्भ पश्चात उठ प्रयन श्रवधारण ।

5. हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहेताएं हटाना) ग्रध्यादेश, 1971 निरसन भीर 1971 町 4 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है। व्यावति ।

> ए से निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त ग्रध्यादेश के प्रधीन की गई कोई बात या कारंबाई इस ग्रधिनियम के ग्रधीन की गई समझी जाएगी मानों यह ग्रधिनियम 25 जनवरी, 1971 को प्रारम्भ हो गया या।

शिमला-2, 4 फरवरी, 1986

सं 0 डी 0एल 0 आर 0 - अनुवाद अधिप्रमाणन - 5/84 - - हिमा चल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश स्टेट लैजिस्लेचर आफिसर्ज, मिनिस्टर्ज एण्ड मैम्बर्ज (मैडिकल फैसिलिटीज) ऐक्ट, 1971 के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्त, हिमाचल प्रदेश में एतदद्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

म्रादेश द्वारा, कुलदीप चन्द सूद, संचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रवेश राज्य विधान सभा ग्रधिकारी, मन्त्री ग्रीर सदस्य (चिकित्सा सुविधा) ग्रिधिनियम, 1971

(1971 का ग्रधिनियम संख्यांक 6)

(15 ग्रक्तूबर, 1984 को यथा विद्यमान)

(22 म्रप्रैल, 1971)

हिमाचल प्रदेश राज्य में कुछ पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को विकित्सा की सुविधा का विस्तार करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के वाईसर्वे वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह श्रिधिनियमित हो :--

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा अधिकारी, संक्षिप्त नाम मन्त्री और सदस्य (चिकित्सा मुविधा) अधिनियम, 1971 है। श्रीर प्रारम्भ।
 - (2) यह 25 जनवरी, 1971 को प्रवृत्त हुग्रा समझा जायेगा।
- 2. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी ग्रन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई पद तत्समय धारण करता है, ग्रपने लिए ग्रीर ग्रपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए ऐसी चिकित्सा सुविधा का हकदार होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, प्रयात्:—
- चिकित्सा सुविधा ।

- (1) हिमाचल प्रदेश विधान सभा का प्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष;
- (2) हिमाचल प्रदेश राज्य का मन्त्री या उप-मन्त्री; या
- (3) हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य।

1

- (2) अस्पतालों में स्थान और चिकित्सीय उपचार की बाबत सभी नियम, जो उप-धारा (1) में विजित अधिकारियों को इस अधिनियम के आरम्भ से ठीक पूर्व लागू थे, तब तक लागू रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन नियम नहीं बना दिए जाते हैं।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के परवात् ययाशक्यशीध्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सब में हो, कुल चौदह दिन की अविधि के लिए रखा जाएगा । यह अविधि एक सब में या दो या अधिक आनुक्रमिक सबों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सब के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या उपर्युक्त सब के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्यश्वात् वह ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व

विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभाव होने से उसके भ्रधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़गा।

शिमला, 4 फरवरी, 1986

सं0 ही 0 एत 0 झार 0- झनुवाद अधिप्रमाणन 2/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि सैंलरीज एण्ड झलाउं सिज आफ मिनिस्टर्ज (हिमाचल प्रदेश) ऐक्ट, 1971" के अधिप्रमाणित हिन्दी ह्पान्तर को राजपन्न, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं भौरयह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

मादेश द्वारा, कुलदीप चन्द सूद, सविव ।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971

(1971 का श्रधिनियम संख्यांक 3)

(20 सितम्बर, 1984 को यथाविद्यमान)

(22 प्रमेल, 1971)

हिमाचल प्रदेश राज्य में मंत्रियों के वेतन ग्रीर भत्तों का उपवन्ध करने के लिए ग्रिधिनियम।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह श्रधिनियमित हो :—

- 1. (1) इस ग्रधिनियम का संक्षिप्त नाम मंत्रियों के वेतन श्रोर भत्ता (हिमाचल संक्षिप्त नाम प्रदेश) ग्रधिनियम, 1971 है। ग्रीरप्रारम्म।
- (2) यह धारा 6 के सिवाए, जो 20 दिसम्बर, 1963 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी, 25 जनवरी, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1

- 2. इस ग्रधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो, परिमामाएं।
 - (क) "गृह" के अन्तर्गत कर्मवारिवृन्द आवास गृह और उससे अनुलग्न अन्य भवन और उनके उद्यान हैं;
 - (ख) किसी गृह के सम्बन्ध में "प्रनुरक्षण" के प्रत्यांत स्थानीय रेट ग्रीर करों का तथा विद्युत ग्रीर जल के अभारों का संदाय होगा; ग्रीर
 - (ग) "मंत्री" से मंत्रि-परिषद् का सदस्य श्रिष्ठित है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।
- 3. प्रत्येक मंत्री को प्रतिमास एक हजार पांच सौ रुपए की दर से वेतन, श्रौर मुख्य मंत्रियों का मंत्री को, उसके ग्रतिरिक्त प्रति मास पांच सौ रुपए की दर से सत्कार भत्ता संदत्त किया वेतन। जाएगा।
- 4. प्रत्येक मंत्री को एक निःशुल्क सुसजित गृह दिया जाएगा, जिसके अनुरक्षण का मंत्रियों के प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, या ऐसे गृह के स्थान पर उससे प्रति मास तीन निवास स्थान। सी ६४ए से अनिधक भत्ता, जैसा सरकार प्रत्येक मामले में नियत करे, दिया जाएगा। राज्य सरकार उसे दिए गए गृह का उसे, उसके मंत्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनिधक अविध के लिए निःशुल्क अधिभोग करने की अनुज्ञा भी दे सकेंगी।

स्पष्टीकरण:—मंत्री ऐसे किसी मामले में जहां उसको निवास के लिए ब्रावंटित गृह का मानक किराया तीन सौ रुपए प्रति मास से श्रधिक हो किसी संदाय के लिए ध्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा।

5. (1) प्रत्येक मंत्री एक कार का, जिसके धनुरक्षण और नौदन का व्यय राज्य बाहन भत्ता। सरकार बहन करेगी, या उसके स्थान पर प्रति मास पांच सौ रूपए बाहन भत्ते का हुकदार होगा:

परन्तु मंत्री तारा उपयोग की जाने वाली राज्य कार के अनुरक्षण और नोदन का व्यय प्रतिमास पांच सौ रूपये की सीमा के प्रधीन नहीं होगा।

(2) यदि मंत्री स्वयं अपनी मोटर कार का उपयोग करता है तो वह उप-धारा(1) में उपबन्धित वाहन भत्ते के स्थान पर सरकारी व्यय पर एक चालक (शोफर) की सेवा का विकल्प कर सकेगा ।

रेल द्वारा या वायुमागं द्वारा नि:शुल्क याता ।

5-क. प्रत्येक मंत्री को उसकी पदावधि के दौरान कुपन पुस्तकें प्रदान की जाएंगी जो उसे और उसकी पत्नी या पति को या उसकी देखमाल और सहायता के लिए उसके साथ याता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय भारत में किसी भी रेल द्वारा भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारी किए गए चाल सवारी डिब्बा टैरिफ के अनसार पहले दर्जे में याता करने का हकदार बनाएगा, परन्तु ऐसी याता की कुल दूरी किसी वित्तीय वर्ष में बीस हजार किलोमोटर से प्रधिक नहीं होगी:

परन्त मंत्री भीर उसकी पत्नी या पनि या उसकी देखभाल या सहायता के लिए उसके साथ याता करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उन कानों पर, जिन ह लिए वह हकदार है, वाता-नकलित रेल सवारी डिब्बे में याता कर सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि याता उसके द्वारा वायु मार्ग द्वारा को जाती है तो उसे ऐसो याता के लिए पहले दर्जे के एक टिकट के किराए के बराबर रकम संदत्त की जाएगी भीर यदि उत्तके साथ उसकी पत्नी या पति या उसकी देखमाल या सहायता के जिए कोई म्रन्य व्यक्ति याता करता है तो उसे ऐसी याता के लिए पहले दर्जे के दो टिकट के बराबर रकम संदत्त की जाएगी:

परन्तु यह स्रौर कि कूपन पर या वायु मार्ग द्वारा की गई याता के लिए संदेय कुल रकम किसी वित्तीय वर्ष में पहले दर्जे के रेल टिकट से बीस हजार किलोमीटर के लिए संदेय रकम से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:-इस घारा के अधीन कूल दूरी का अवधारण करने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्यान समा ग्राञ्च और उगाध्यक्ष के वेतन ग्रिधिनियम, 1971 की बारा 10-क, या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों हे भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 6 या उप-मंत्रियों के वेतन और भता (हिमावन प्रदेश) ग्रधिनियम, 1971 को धारा 6-क के प्रजीत रेत या वाय मार्ग द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में की गई यावा की दूरी को हिसाब में जिया जारगा।

1971 町子

1971 町8 1971 新 5

मंत्री द्वारा सरकारी मोटर कार के उपयोग का विधिमान्य-करण।

6. ऐसे किसी मंत्री के वारे में जिस ने मंत्रियों के वेतन और भता (हिमाचन प्रदेश) मधिनियम, 1963 के प्रधीन उसे अनुज्ञेय वाहन भत्ता 20 दिसम्बर, 1963 के पश्चात् नहीं लिया है और सरकारी मोटर कार का उपयोग किया है यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी मोटर कार का उपयोग वैसे हो किया है मानों कि उसके अनरक्षण और नोदन का व्यय सरकार द्वारा किया गया है।

1963 和 2

W.

7. प्रत्येक मंत्री को मोटर कार का कय करने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के मोटर कार के रूप में ऐसी राशि और ऐसी शतों के प्रधीन रहते हुए, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों मंत्री को उद्यार द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी जिससे कि वह अपने पद के कर्त व्यों का सुविधा पूर्वक श्रीर दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके। दिया जाना।

क्य के लिए

7-क. मंत्री को गृह निर्माण के लिए या बने बताए गृह का ऋष करने के लिए गृह निर्माण प्रतिसंदेय श्रीप्रम के रूप में ऐसी राशि और ऐसी शर्तों के श्रधीत रहते हुए, जैसी इस श्रीप्रम। निमित बनाए गए नियमों दारो अवधारित की जाए मंदत्त की जा सकेगी।

8. (1) प्रत्येक मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी स्थान पर या अपने स्थाई टेलीफोन का निवास के स्थान पर, यदि ऐसे स्थान पर ऐसी सुविधा साधारण दरों पर ग्रीर कोई ग्रतिरिक्त निःशुक्क व्यय उपगत किए विना उपलब्ध है, जैसा भी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक टेली- संस्थापन फोन संस्थापित कराने का हकदार होगा और संस्थापन के स्थान के ऐसे विनिर्दिष्ट किए जाने पश्चात् ऐसे टेलोकोन के प्रथम संस्थापन के लिए प्रभार, प्रतिभूति तिक्षेर और वार्षिक किराया, राज्य सरकार द्वारा बहुन किया जाएगा और अन्य सभी व्यय जैसे कि वे जो स्थानीय या बाह्य कालों से मंत्रियत है, मंत्री दवारा संदत्त किए जाएंगे:

मंस्यापत ।

परन्तु मंत्री द्वारा स्थानीय या बाहय कालों पर किसी मास में उपगत व्यथ की प्रतिपूर्ति ग्रिधिकतम बार मो रुगए क अधीन रहने हुए, सरकार द्वारा की जाएगी :

परन्तु यह और कि मंत्री उसे प्रदान की गई टैनीफीन सुविधा का, उसके मंत्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनिधिक भवाध के लिए उपयोग कर सकेगा।

- (2) वे सभी व्यव, जो मंत्री द्वारा उप-वारा (1) के अवीन मंस्यापित टेलीफोन के संबंध में संदेय है, उसके द्वारा सीधे नकद संदत्त किए जाएंगे और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह राज्य सरकार द्वारा उसे राज्य सरकार से देय किसी रकम में समायोजित किया जाएगा।
- 9. इस अधिनियम के अधीन वेतन और भता पाने वाला कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा उपबंधित विधि में से ऐसी सभा की अपनी सदस्यता को बाबत वेतन भीर भत्ते के रूप में कोई राणि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

मंत्रियों द्वारा विधान सभा के सदस्य के रूप में वेतन भौर भत्तों का न लिया जाना ।

9-क. इस अधिनियम के अधीन मंत्री को संदेय वेतन और भत्ते और उसे अनुजेय नि:शुरूक सुसज्जित गृह और अन्य परिलब्धियां आय-करसे अपर्वजित होंगी जो राज्य सरकार कारा संदेय होगा।

वंतन, भत्ते ग्रीर परि-लब्धियों का ग्राय-कर से भ्रपवर्जित होना ।

स्पन्दीकरण: राज्य द्वारा संदेय आय-कर की रकम ग्राय-कर के लिए निर्धारित ग्राय की प्रथम स्लैब होगी, अर्थात इस रकम के निर्धारण में संबंधित मंत्री की भाग के अन्य स्रोतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मित्रों की की भाष्रसंजना का उसका निष्या यक सःध्य होता ।

रतः जह तारीज, जिसकी कि कोई व्यक्ति भंती बनता है या बना नहीं रहता है, हिमालल नियुक्ति भादे प्रदेश सरकार के शासकाय राजात में प्रकाशित की जाएगी धीर ऐसी कोई प्राथमाना इस घोष्ट्रियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस तब्य का निवनायक सावव होगी कि प्रश्न जम तारोख को मंत्री बना या बना नहीं रहा।

नियम बनाने या अयोक्त करने को शक्ति।

11. मंतियों के माता धीर दैनिक घरने ऐसे निगमों क धनुतार निनियमित किए आएचे जैसे राज्य सरकार द्वारा समग-समग पर बनाए या धंगीकत किए जाएं :

परन्तु राज्य कार द्वारा की गई यादाओं के सम्बन्ध में कोई मील मत्ता था यादा धला पभावं नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे नियम राज्य सरकार द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से भी बनाए जा

निरसन सीर अवस्ति।

- 12. (1) मंत्रियों के वेतन और मता (हिमाचल प्रदेश) प्रधिनियम, 1963 ग्रीर मंत्रियों 1963 77 2 के वेतन भीर भता (हिमाचल प्रदेश) छाध्यादेश, 1971 को एतद्बारा निरसित किया 1971 का। जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए शी, उन्त प्रधिनियम धीर प्रध्यादेश द्वारा या क प्रधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई या की गई तार्ल्पयत कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत बनाए गए या जारी किए गए कोई नियम, श्रधिमुचनाएं या श्रादेश भा हैं) इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

शिमला-2, 4 फरवरी, 1986

सं0 डी0 एल0 आर0-अनुवाद श्रधिप्रमाणन 3/84. -- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचन प्रदेश राजभाषा (ग्रन्पूरक उपबन्ध) ग्रिधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शनितयों का प्रयोग करते हुए दि हिमाचल प्रदेश लिजसलेटिव भसेम्मली स्वीकर्ज एण्ड डिप्टी स्वीकर्ज सैलरीज ऐक्ट, 1971 के अधिप्रवाणित, हिन्दी स्पान्तर को राजपन्न, हिमाचल प्रदेश में एतददारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधि-नियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

> श्रादेश दारा. हस्ताक्षर, (क्लदीप चन्द सुद), सचिव ।

ँ हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971

(1971 का भ्रधिनियम संख्यांक 4)

(20 सितम्बर, 1984 को यथा विद्यमात)

(22 मप्रैल, 1971)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा थे प्रध्यक्ष भीर उपाध्यक्ष के वेतन भीर भत्तों के लिए उपाबन्ध करने थे लिए प्रार्धानयम।

भारत गणराज्य क बार्टमर्वे वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा दारा निस्त-लिखित इप में यह श्रीधानयीमन हो---

1. (1) इस अधिनियम का मंश्रिष्त नाम हिमाचल प्रवेश विधान सभा प्रध्यक्ष संक्षिप्त नाम भीर उपाध्यक्ष नेतन अधिनियम, 1971 है। भीर प्रारम्भ ।

(2) यह 25 जनवरी, 1971 में प्रवृत्त हुधा समझा जाएगा, किन्तु धारा 5, 18 जनवरी, 1970 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

गरिमामाएं।

- (क) "गृह" के अलगंत कर्म प्रित्व आवास गृह और उस्में अनुलग्न भारा भवन और उनके उद्यान हैं,
- (ख) किसी गृह के सम्बन्ध में "ग्रनुरक्षण" क श्रन्तर्गत स्थानीय रेट घीर करों का तथा विद्युत ग्रीर जल क प्रभारों का संदायहोगा।
- 3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रध्यक्ष को पन्द्रह सौ कार्य प्रति भास की यह से भाष्या का वेतन संदत्त किया जाएगा और इसके अतिरिक्त उसे सरकार द्वारा शिमला में निःमुल्क वेतन। सुचित्रत गृह दिया जाएगा जिसके प्रतृत्थण का प्रभार राज्य सरकार यहन करेगी। राज्य सरकार उसे उसके प्रध्यक्ष न रहने की तारीज से पन्द्रह दिन से प्रनिधक की प्रविध तक गृह का निःमुल्क अधिकोगी वने रहने की अनुमाभी दे सकेगी।

3-क. ब्रध्यक्ष की घारा 3 के श्रधीन उसको धनुत्रेय नेतन और भ्रत्य परिजिक्षमा संस्कार भत्ता । के मनिरिक्त चार भी रुपये प्रतिमाम की दर्ग मन्कार भना थिया जाएगा ।

4. हिमाचल प्रदेश विद्यान सभा के उपाध्यक्ष को एक हमार पांच सौ भाग पनि गाम हापाध्यक्ष की दर में देनन संदन किया जाएगा थीर इसक श्रीनिश्चत उसे सरकार द्वारा भिगना में नेतन। निःशुल्क सुमुज्जित गृह दिया जाएगा जिसके धनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार वहन करेगी या उसक बदने में उसे तीन सौ रुपये प्रति माम से श्रात्धिक ऐसा भत्ता जो राज्य सरकार तियत करें, संदन किया जाएगा। राज्य सरकार उसे, उसक उपाध्यक्ष न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अन्धिक की अन्धि तक गृह का निःशुल्क श्रीधभोगी बन रहने में सकेगी।

स्पट्टीकरणः उपाध्यक्ष किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से वाथी नहीं होगा, यांव

उसकी निवास के लिए भाषांटित गृह का मानक किराया एक सी पच्चास रुपये प्रतिमास से प्रधिक हो जाता है।

18-2-70 खें 24-1-71तक उपाध्यक्ष का वेतन । 5. उपाध्यक्ष को 18 फरनरी, 1970 से 24 जनवरी, 1971 तक सात सौ रुपये प्रतिमाम की दर से वेतन संदत्त किया जाएगा और वह विधान सभा के श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और अता (हिमाचल प्रदेश) श्रिधिनियम, 1963 के अधीन पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से श्रपने द्वारा पहले लिए गए वेतन को घटाने के पश्चात् दो सौ रुपये प्रति मास की दर से बकाया लेने का हकदार होगा।

1963

वाइन भत्ता ।

6. (1) ग्रध्यक्ष श्रीर उपाध्यक्ष, प्रत्येक, एक कार का उपयोग करने का, जिसके सनुरक्षण भीर नोदन का व्यय राज्य सरकार बहुन करेगी या उसके बदले में पांच सौ रुपये प्रति-मास वाहन भन्ते का हकदार होगा:

परन्तु ग्रहणक्ष या उपाध्यंक्ष के उपयोग में को राज्य की कार के अनुरक्षण और नोदन के व्यय पांच सो रुपये की सोमा के अधीन रहते हुए नहीं होंगे।

(2) यदि यह अपनी मोटर कार का उपयोग करता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उप-धारा (1) में उपबन्धित वाहन भन्ने के स्थान पर सरकारी व्यय पर एक चालक की सेवाओं के लिए विकल्प दे सकेगा।

श्रघ्यक्ष श्रोर उपाध्यक्ष को उद्यार का श्रीग्रम। 7. श्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष को मोटर कार खरीदने के लिए प्रति संदेय प्राग्निम के रूप में ऐसी धनराशि और ऐसी शती के प्रधीन रहते हुए जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए नियमों द्वारा श्रवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी जिससे वर्ष्ट्र अपने पद के कर्त्तंच्यों का सुविधापूर्वक और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सर्के।

गृह निर्माण भग्निम । 7-क. भ्रष्टियक्ष भीर उपाध्यक्ष को गृह निर्माण के लिए या बने बनाए गृह को ऋष करने के लिए प्रतिसंदेय श्रियम के इन में ऐसी धनराणि भीर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी इस निमित बनाए गए नियमों द्वारा श्रवधारित की जाए, दी जा सकेगी।

टेलीफोन की निःशुल्क स्थापना । 8. (1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रत्येक, अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर या अपने स्थायी निवास स्थान पर जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे, एक टेलीफोन स्थापित कराने का, यदि ऐसे स्थान पर, ऐसी सुविधा साधारण दरों पर और कोई अतिरिक्त खर्च उपगत किए बिना उपलब्ध है, हकदार होगा, और स्थापना के स्थान को इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसे टेलीफोन की प्रथम स्थापना का प्रभार, प्रतिभूति-निक्षेप और वाषिक किराया राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और सभी अन्य व्यय जैसे कि स्थानीय एवं बाह्य कालों से सम्बन्धित व्यय, यथास्थित, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा, संदत्त किए जाएंगे:

परम्तु किसी मास में स्थानीय या बाह्य कालों पर, यथास्थिति, ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा उपगत व्ययको प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा, चार सौ रुपये की ग्रधिकतम सीमा के ग्रधीन रहते हुए, की जाएगी:

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष उन्हें प्रदान की गई टेलीफोन सुविधा का उपयोग उनके, यथास्थिति, ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहने की तारोख से ग्रधिक से ग्रधिक पन्द्रह दिन तक की ग्रविध तक करते रह सकेंगे।

रेल द्वारा या

द्वारा नि:शुल्क

मागं

वाय

(2) ऐसे सभी व्यय, जो उप-धारा (1) के ग्रधीन स्थापित टेलीफोन के सम्बन्ध में ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा देय है, यथास्थिति, ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा सीधे नकद रूप में संदत्त किए जाएंगे ग्रीर यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष, को शोध्य किसी राशि के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा समायोजित किया जा सक्ता।

9. ग्रध्यक्ष कोई वृत्ति नहीं करेगा या किसी व्यापार में नहीं लगेगा श्रीर ग्रध्यक्ष ग्रध्यक्ष कोई ये रूप में ग्रपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा वृद्धि नहीं 971 का 7 सदस्य (निर्म्हताश्रों का हटाना) ग्रिधिनियम, 1971 में यथा परिभाषित प्रतिकरात्मक करेगा। भत्तों म भिन्न कोई धन प्राप्त नहीं करेगा।

> 10. श्रध्यक्ष ग्रीर उपाध्यक्ष का यात्रा ग्रीर दैनिक भत्ता ऐसे नियमों क ग्रनुसार विनियमित यात्रा भत्ता । होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर विरचित या ग्रंगीकृत करे:

भरन्तु राज्य को कार द्वारा को गई या**द्वा के** लिए मोल भताया याद्वा भता प्रमार्थ नहीं होगा।

10-क. ग्रध्यक्ष ग्रीर उपाध्यज्ञ, प्रत्येक, को उसकी पदावधि के दौरान कूपन पुस्तकें प्रदान की जाएगी जो उसे श्रीर उसकी पत्नी या पित को या उसकी देखमाल ग्रीर सहायता के लिए उसके साथ याद्रा करने वाले किसी ग्रन्थ व्यक्ति को किसी भी समय भारत में किसी भी रेल द्वारा भारत सरकार के रेलवे मन्द्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारो किए गए चालू सवारी डिब्बा टैरिफ के ग्रनुसार पहले दर्जे में याद्रा करने का हकदार बनाएगी, परन्तु ऐसी याद्रा की कुल दूरी किसी वित्तीय वर्ष में बीस हजार किलोमीटर से ग्रधिक नहीं होगी:

2

जाएगा।

परन्तु, यथास्थिति, ग्राध्यक्ष या उपाध्यक्ष ग्रीर उसकी पत्नी या पति या उसकी देख भाल या सहायता के लिए उनके साथ याता करने वाला कोई ग्रन्थ व्यक्ति उन कूपनों पर, जिनके लिए वे हकदार हैं, वातानुकुलित रेल सवारी डिब्बे में याता कर सकेंगे:

परन्तु यह श्रीर कि यदि याना उसके द्वारा वायु मार्ग द्वारा की जाती है तो उसे ऐसी याना के लिए पहले दर्जे के एक टिकट के किराया के बराबर रकम संदत्त की जाएगी भीर यदि उसके साथ उसकी पत्नी या पित या उसकी देख-भाल या सहायता के लिए कोई श्रन्य व्यक्ति याना करता है तो उसे ऐसी याना के लिए पहले दर्जे के दो टिकटों के किराये के बराबर रकम संदत्त की जाएगी:

परन्तु यह और कि कूपन पर या वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम किसी वित्तीय वर्ष में पहले दर्जे के रेल टिकट से बीस हजार किलोमीटर के लिए संदेय रकम से ग्रधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण:—इस द्वारा के ब्रिधीन कुल दूरी का अवधारण करने के लिए मंत्रियों 1971 का 3 के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 5-क, या हिमाचल 1971 का 8 प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के वेतन और पेंन्श्रन) अधिनियम, 1971 को धारा 6 की उप-धारा (1) या उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 को धारा 6-क के अधीन रेल या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क याता की सुविधा का उपभोग करके किसी वित्तीय वर्ष में की गई याता को दूरी को हिसाब में लिया

अध्यक्ष भीर उपाध्यक्ष सभा के सदस्य के रूप में कोई वेतन नहीं लेंगे। वेतन, भत्तों भाय-कर न लगना ।

11. भ्रष्ट्यक्ष भीर उपाध्यक्ष ऐसी निधि में से, जो सभा बारा, ऐसी सभा की उनकी सदस्यता की बाबत वेतन या भत्ता के रूप में उपबन्धित है, कोई राणि प्राप्त करने के इकदार नहीं होंगे।

11-क. इस ग्रधिनियम के भ्रधीन ग्रध्यक्ष भीर उपाध्यक्ष की संदेय वेतन भीर भत्तों परि- भौर उन्हें भनुज्ञेय नि:शुल्क सुसज्जित गृह भौर भन्य परिलब्धियों पर भाय-कर नहीं लगेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

स्वव्होकरण:---राज्य सरकार द्वारा संदेय ग्राय-कर की रकम श्राय-कर के लिए निर्धारित भाय का पहला स्लैब होगी अर्थात् इस रकम का निर्धारण करने में, श्रध्यक्ष भीर उपाध्यक्ष के श्राय के श्रन्य स्रोतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग्रध्यक्ष ग्रादि की नियक्ति मधिस्चना उसका निश्चायक साक्ष्य होना । नियम बनाने की शक्ति।

12. वह तारीख, जिसको कोई व्यक्ति भन्यक्ष या उपाध्यक्ष बनता है या नहीं रहना है, हिमाचल प्रदेश राज्य के शासकीय राजपत्न में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी कोई ग्रधिसुचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह इस ग्रधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए उस तारीख को ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना या नहीं रहा ।

- 13. (1) राज्य सरकार इस ग्रधिनियम में प्रयोजनों को कार्यान्वित करते के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के शासकीय राजपत में अधिस्वना द्वारा नियम बना सकेंगी।
- (2) इस श्रधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् ययाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

निरसन ग्रीर ध्यावृत्ति ।

- 14. (1) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) भिधिनियम, 1963 भीर विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वैतन भीर भत्ता (हिमाचल प्रदेश) ग्रध्यादेश, 1971 कः एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरप्तित अधिनियम या अध्यादेश द्वारा या उस के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई या की गई तात्पपित कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत बनाया गया या जारी किया गया कोई नियम ग्रधिस्चना या भादेश है) इस ग्रधिनियम के ग्रधीन की गई समझी जाएगी।

दिनांक 4 फरवरी, 1986

संख्या डी 0 एल 0 ग्रार 0 ग्रनुवाद ग्रधिप्रमाणन 1/84.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (ग्रनुपूरक उपबन्ध) श्रिधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिमाचल प्रदेश ग्राफिशियल लैंग्वेज ऐक्ट, 1975 के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्न, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

> श्रादेश द्वारा. हस्ताक्षर, (कूलदीप चन्द सूद), सचिव।

1963

1971

हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1975

(1975 का अधिनियम संख्यांक 1)

(20 सितम्बर, 1984 को यथाविद्यमान)

(20 फरवरी, 1975)

हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने बाली भाषा के रूप में हिन्दी को अंगीकृत करने का उपबन्ध करने के लिए सिंधनियम ।

भारत गणराज्य के छब्बीसर्वे वर्षं में हिमाचल प्रदेश विद्यान समा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह प्रधिनियमित हो :--

1. (1) इत प्रधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1975 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह 1 जनवरी, 1975 से प्रवृत्त हुम्रा समझा जाएगा ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यया अपेक्षित न हो,-

(क) "हिन्दी" से वह हिन्दी अभिश्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है; (ख) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश की सरकार अभिश्रेत है।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य की राजभाषा हिन्दी होगी।

परिभाषाएं।

संक्षिप्त नाम,

विस्तार ग्रीर

प्रारम्म ।

हिन्दो का राज्य की राजभाषा होना ।

4. राज्य सरकार, श्रविसूचना द्वारा, समय-समय पर, यह निदेश दे सकेगी कि हिन्दी राज्य के ऐसे शासकीय प्रयोजनों के लिए और ऐसी तारीख से, जो श्रविसूचना में विनिदिष्ट की जाए, प्रयोग की जाएगी।

राज्य सरकार की उस शासकीय प्रयोजन को प्रधिसूचित करने की शास्त्रि जिसके लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

5. ऐसी तारीख को और से जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें:—

(क) राज्य की विधान सभा में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों और उनके प्रस्तुत किए जाने वाले सभी संशोधनों में;

विधेयकों ग्रादि में प्रयोग की जाने वाली

भाषा।

- (ख) राज्य की विधान सभा द्वारा पारित सभी ग्रधिनियमों में;
- (ग) संविधान के धनुक्छेद 213 के प्रधीन राज्यपाल द्वारा प्रक्यापित सभी धन्यादेशों में:
- (घ) संविधान के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के भधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों भौर उपविधियों में;

प्रयोग की जाने वाली भाषा हिन्दी होगी:

परन्तु राज्य सरकार ऊपर खण्ड (क) से (घ) तक में निर्दिष्ट किन्हीं प्रयोजनीं की बाबत भिन्न-भिन्न तारीखें नियत कर सकेगी।

राज्य की विधान सभा में अंग्रेजी का प्रयोग बना

रहना।

6. जब तक राज्य सरकार धारा 4 के ग्रधीन ग्रधिसूचना द्वारा ग्रन्थया निवेश न दें, राज्य की विधान सभा में कार-बार के संव्यवहार के लिए राज्य की राजभाषा के ग्रतिरिक्त ग्रंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा।

राज्य में प्रयुक्त किन्हीं भाषाभों में भ्रभ्यावेदन करने का व्यक्तियों का मधिकार।

राज्य में 7. इस अधिनियम की कोई बात किसी शिकायत के प्रतितोष के लिए, राज्य के प्रयुक्त किसी प्रधिकारी या प्राधिकारी को राज्य में प्रयुक्त किसी प्रन्य भाषा में अभ्याबेदन देने में भाषामों में किसी व्यक्ति को विवर्जित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

निरसन भीर व्यावृत्ति । 8. (1) पंत्राब राजमाषा ग्राधिनियम, 1960, जैसा कि वह पंजाब पुनगैठन ग्रिधि-नियम, 1966 की धारा 5 के ग्रधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्र में लागू है, ग्रौर हिमाचल प्रदेश लैंग्वेजिज (बिल्ज एण्ड एक्ट्स) ऐक्ट्स, 1952, जैसा कि वह 1 नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में प्रवृत्त है, एतद्दारा निरसित किया जाता है।

1960 কা 28 1966 কা 31 1952 কা 2

(2) इस अधिनियम द्वारा निरसन का प्रभाव निरसित अधिनियमों द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई किसी बात या किसी कार्रवाई पर या ऐसी किसी घटना पर, जो निरसित अधिनियम के परिवर्तन से हुई हो, नहीं पड़ेगा।

शिमला-2, 4 फरवरी, 1986

सं0 डी 0 एल 0 ग्रार 0-ग्रनुवाद ग्रधिप्रमाणन 4/84.—हिमाचल प्रदेश क राज्यवाल, हिमाचल प्रदेश राज्याला (ग्रनुपूरक उपबन्ध) ग्रधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि सैलरोज ऐण्ड ग्रलांक्रिज ग्राफ डिप्टी मिनिस्टरजं (हिमाचल प्रदेश) ऐक्ट, 1971 के ग्रधिप्रमाणित हिन्दो रूगांतर को राजपत्न, हिमाचल प्रदेश में एतदद्वारा प्रकाशित करते हैं ग्रौर यह उक्त प्रधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

ब्रादेग दारा, कुत्रदोन चन्द सूद, सचित्र विधि ।

रूप-मंतियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971

(1971 का ग्रधिनियम संख्यांक 5)

(20 मितम्बर, 1984 को यथा विद्यमान)

(22 चप्रैल, 1971)

हिमाचल प्रदेश राज्य में उप-पंत्रियों के वेतन ग्रीर मत्तों का उपबन्ध करने के लिए ग्राथिनियम ।

भारत गणराज्य के बाईसर्वे वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिबित रूप में यह ग्रिधिनियमित हो:--

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उप-मंत्रियों के वेतन भीर भता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 है।

संक्षिण्त नाम भौर प्रारम्भ ।

- (2) यह 25 जनवरी, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, किन्तु धारा 4, भठारह फरवरी, 1970 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और धारा 7 मठारह मार्च, 1967 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।
 - 2. इस प्रधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से ग्रन्यया ग्रपेक्षित न हो--

परिभाषाएं ।

- (क) "गृह" के ग्रन्तर्गत कर्मचारिवृन्द ग्रावास गृह ग्रौर उसक्षे ग्रनुलग्न ग्रन्थ भवन ग्रौर उनके उद्यान हैं; ग्रौर
- (ख) किसी गृह के सम्बन्ध में 'श्रनुरक्षण' के श्रन्तगैत स्थानीय रेट ग्रीर करों का तथा विद्युत ग्रीर जल के प्रभारों का संदाय होगा।
- 3. प्रत्येक उप-मन्त्री को प्रतिमास एक हजार चार सौ रुपये की दर से वेतन दिया जाएगा जो भाय-कर से ग्रपर्वाजत होगा।

4. प्रत्येक उप-मंत्री को 18 फरवरी, 1970 से 24 जनवरी, 1971 तक प्रति मास सात सौ रूपए की दर से वेतन संदत्त किया जाएगा ग्रीर वे मंत्रियों के वेतन ग्रीर भत्ता (हिमाचल प्रदेश) ग्रीधिनियम, 1963 क ग्रधीन प्रति मास पांच सौ रुएए की दर से ग्रपन द्वारा शहले लिए गए वेतन को घटाने के प्रचात् प्रति मास दो सौ रूथए को दर से बकाया लेने के हकदार होंगे।

5. प्रत्येक उप-मन्त्री ग्रपनी पदावधि के दौरान श्रीर उसके ठोक पश्चात् पन्द्रह दिन की श्रवधि तक सुसज्जित श्रीर राज्य सरकार द्वारा श्रनुरक्षित गृह का निवास के लिए (श्राय-कर मुक्त) उपयोग करने का हकदार होगा या उसके स्थान पर उसे प्रतिमास एक सौ पच्चास रुपए से अनिधिक का ऐसा भता संदत्त किया जाएगा जैसा राज्य सरकार नियत करे।

उप-मंत्रियों का बेतन ।

> 18 फरवरी 1970 से, 24 जनवरी 1971 तक उप-मंत्रियों

का वेतन । उप-मंत्रियों के निवास स्थान ।

स्पष्टीकरण:--उप-मंत्री ऐसे मामले में जहां उसको निवास के लिए ग्रावंटित गृह का मानक किराया एक सौ पच्चास रुपए प्रति मास से प्रधिक हो, किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा।

बाहन भता।

6. (1) प्रत्येक उप-मन्त्री एक कार का, जिसके अनुरक्षण श्रीर नोदन का ब्यय राज्य सरकार वहन करेगी, या उसके स्थान पर प्रतिमास तीन सौ ठपए वाहन भत्ते का हकदार होगा:

परन्तु उप-मन्त्री द्वारा उपयोग की जाने वाली राज्य कार क ग्रन्रक्षण ग्रौर नोदन का व्यय प्रति मास तीन सौ रुपए की सीमा के भवीन नहीं होगा।

(2) यदि उप-मन्त्री भ्रपनी स्वयं की मोटर कार का उपयोग करता है तो वह उप-धारा (1) में उपबंधित वाहन मत्ते के स्थान पर सरकारी व्यथ पर एक चालक (शोफर) की सेवा का विकल्प दे सकेगा।

रेल द्वारा या वाय-मार्ग द्वारा नि:-

6-क. प्रत्येक उप-मन्त्री को उसकी पदावधि के दौरान कूपन पुस्तकों प्रदान की आएंगी जो उसे श्रीर उसकी पत्नी या पति को या उसकी देख-भाल श्रीर सहायता क लिए उसके साथ याता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय भारत में किसा भी शहक याला। रेल द्वारा भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारी किए गए चाल सवारी डिब्बा टैरिफ के अनुसार पहले दर्जे में याचा करने का हकदार बाएगा, परन्त ऐसी याता की कुल दूरी किसी वित्तीय वर्ष में बीस हजार किलोमोटर से श्रीवक नहीं होगी:

> परन्तु उप-मन्त्री ग्रीर उसको परनी या पति या उसकी देख-भाल या सहायता के जिए उसके साथ याता करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उन क्पनों पर, जिलके लिए वह हुकदार है, वातानकुलित रेल सवारी डिब्बे में यात्रा कर सकेगा:

> परन्त यह और कि यदि याचा उसके द्वारा वायु-मार्ग द्वारा की जाती है तो उसे ऐसी याचा के लिए पहले दर्जे के एक टिकट के किराएँ के बराबर रकम संदत्त की जाएगी भीर यदि उसके साथ उसकी पत्नी या पति या उसकी देखभाल या सहायता के लिए कोई अन्य व्यक्ति याता करता है तो उसे ऐसी याता के लिए पहले दर्जे के दो टिकट के बराबर रकम संदत्त की जाएगी:

> परन्तु यह ग्रीर कि कृपन पर या वायु-मार्ग द्वारा की गई याता के लिए संदेय कूज रकम किसी वित्तीय वर्ष में पहले दर्जें के रेल टिकट से बीस हजार किलोमीटर के लिए संदेय रक्त से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण:--इस धारा के ग्रधीन कुल दूरी का भ्रवधारण करने के लिए मंत्रियो के वेतन श्रीर भत्ता (हिमाचल प्रदेश) श्रधिनियम, 1971 की धारा 5-क, या हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रध्यक्ष ग्रीर उपाध्यक्ष के वेतन ग्रधिनियम, 1971 की धारा 10-क. या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते ग्रीर पेंन्शन) ग्रधिनियम, 1971 की धारा 6 के श्रधीन रेल या वायु-मार्ग द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में की गई यादा की दूरी को हिसाब में लिया जाएगा।

1971年73 1971 का 4

1971 का 8

🗸 7. ऐसे किसी उप-मन्त्री के बारे में जिसने मंत्रियों के वेतन ग्रौर भत्ता (हिमाचल प्रदेश) k1963 का 2 श्रिधिनियम, 1963 के अधीन उसे अनुज्ञेय वाहन मत्ता 18 मार्च, 1967 हे पश्वात् नहीं लिया है भीर सरकारी मोटर कार का उपयोग किया है यह समझा जाएगा कि उसने ए सी मोटर कार का उपयोग वैसे ही किया है मानो उसके अनरक्षण और नोइन का व्यय सरकार द्वारा किया गया हो।

उप - मंत्री द्वारा सरकारी मोटरकार के उपयोग का विधिमान्य-करण ।

8. प्रत्येक उप-मन्त्री को मोटर कार का ऋय करने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के ह्या में ऐसी राशि और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी इस निमित बनाए गए नियमों बारा श्रवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी जिससे कि वह अपने पद के कर्तव्यों का सुविधा-पूर्वक श्रीर दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके ।

मंत्री को उधार दिया जाना ।

मोटर कार

के कम से

लिए उप-

8-क. उप-मन्त्री को गृह निर्माण के लिए या बने बनाए गृह का कय करने के लिए प्रति संदेय ग्रियम के रूप में ऐसी राशि और ऐसी शर्तों के ग्रधीन रहते हुए, जैसी इस निमित बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सन्ति।

गृह निर्माण प्रग्रिम ।

टेलीफोन का

नि:श्रुल्क

संस्थापन ।

9. (1) प्रत्येक उप-मन्त्री भ्रपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी स्थान पर या ग्रपने स्यार्ड निवास के स्थान पर, जैसा भी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक टेलीफोन संस्थापित कराने का हकदार होगा ग्रीर संस्थापन के स्थान के ऐसे विनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात ऐसे टेलीफोन के प्रथम संस्थापन के लिए प्रभार, प्रतिमूर्ति-निक्षेप और वार्षिक किराया राज्य करकार द्वारा वहन किया जाएगा और भ्रन्य सभी व्यय जैसे कि वे जो स्थानीय या बाह्य कातीं से सम्बन्धित हैं. उप-मन्त्री द्वारा संस्त किए जाएंगे :

परन्तु उप-मंत्री द्वारा स्थानीय या बाह्य कालों पर किसी मास में उपगत व्यय की प्रतिपति अधिकतम चार सौ रुपए के अधीन रहते हुए सरकार द्वारा की जाएगी:

परन्तू यह ष्रीर कि उप-मन्त्री उसे प्रदान की गई टेलीफोन सुविधा का उसके उप-मन्त्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से प्रनिधिक प्रविध के लिए उपयोग कर सकेगा।

(2) वे सभी व्यय, जो उप-मन्त्री द्वारा उप-धारा (1) के अधीन संस्थापित देलीकोन के सम्बन्ध में देय है, उस के द्वारा सीधे नकद संदत्त किए जाएंगे और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह राज्य सरकार द्वारा, उसे राज्य सरकार से देग किसी रकम में से, समायोजित किया जाएगा।

9-क. इस अधिनियम के अधीन उप-मन्त्री को संदेय भत्ते और उसे अनुज्ञेय नि:शुल्क सुसज्जित गृह और अन्य परिलब्धियां आय-कर से अपर्वीजत होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संदेय होगा ।

भत्ते ग्रीर परिलब्धियों का ग्राय-कर से भ्रयवर्जित होना ।

स्पष्टीकरण:---राज्य द्वारा संदेय थ्राय-कर की रकम ग्राय-कर के लिए निर्धारित आय की प्रथम स्लैब होगी, ग्रर्थात् इप रकम के निर्धाण में सम्बन्धित उप-मन्त्री की ग्राय के भ्रन्य स्रोतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उप-मंतियों द्वारा विद्यान सभा के सदस्य के रूप में वेतन भौर भत्तों का न लिया 10. इस ग्रीधिनियम के श्रधीन वेतन श्रीर भत्ता पाने वाला कोई व्यक्ति हिमाचल, प्रदेश विधान सभा द्वारा ऐसी सभा की श्रपनी सदस्यता की बाबत वेतन श्रीर भत्ते के रूप में उपबंधित निधि में से कोई राणि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

उप-मंत्रियों की नियुक्ति भादि की स्रिधसूचना का उसका निष्चायक 11. वह तारीख, जिसको कोई व्यक्ति उप-मन्त्री बनता है या बना नहीं रहता है, हिमाचल प्रदेश सरकार के शासकीय राजपद्ध में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी कोई प्रधिसूचना इस प्रधितियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस तब्य का निश्चायक साध्य होगी कि वह उस तारीख को उप-मन्त्री बना या बना नहीं रहा।

नियम इत्यादि बनाने की शक्ति।

साक्ष्य होना ।

12. उप-मंत्रियों के याता धौर दैनिक भत्ते ऐसे निर्नमों क अनुसार विनिधमित किए जाएंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए या धंगी इत किए जाएं:

परन्तु राज्य कार द्वारा की वर्द याताओं के सम्बन्ध में कोई मील मतायायाता भता प्रमार्थ नहीं होना ।

व्यावृत्ति

13. मिन्त्रयों के वेतन भीर भता (हिमाचल प्रदेश) श्रधिनियम, 1963 या मंत्रियों के वेतन ग्रीर भता (हिमाचल प्रदेश) ग्रध्यादेश, 1971 के ग्रधीन की गई या जारी की गई कोई नियुक्ति, ग्रधिमुचना, भादेश, नियम जहां तक कि वह इस ग्रधिनियम के उपबन्धों से भसंगत नहीं है, तब तक प्रवृत्त रहेगी, ग्रीर इस ग्रधिनियम के उपबन्धों के ग्रधीन की गई या जारी की गई समझी जाएगी, जब तक कि उसे इस ग्रधिनियम के उपबन्धों के भधीन की गई या जारी की गई नियुक्ति, ग्रधिमुचना, ग्रादेश या नियम द्वारा ग्रधिकांत नहीं किया जाता है।

1963年1 1971年11